ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-10* November- 2020
Innovation The Research Concept

भारत–नेपाल सम्बन्धों में तनाव – कारण व सुझाव : एक समीक्षात्मक विश्लेषण

Tension in India-Nepal Relations - Causes and Suggestions: A critical analysis

Paper Submission: 15/11/2020, Date of Acceptance: 26/11/2020, Date of Publication: 27/11/2020

बनवारी लाल मैनावत
सह–आचार्य,
राजनीति शास्त्र विभाग,
राजकीय महाविद्यालय, गंगापुर सिटी, राजस्थान, भारत

सारांश

भारत–नेपाल के सम्बन्ध अनौखे प्रकार के सम्बन्ध है। प्राचीनकाल से ही सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जुड़ाव रहा है। इसी को 1950 की पारगमन की संधि ने आगे बढ़ाया है। भारत का रवैया नेपाल के प्रति हमेशा सहयोगात्मक रहा है। यद्यपि कभी–कभी मतभेद भी हुए है। किन्तु उन्हे सुलझा लिया गया है। नेपाल के साथ भारत के सम्बन्ध महत्वपूर्ण है। दो महाशक्तियों (भारत–चीन) के बीच बफर स्टेट के रूप में काम करता है। नेपाल की सुरक्षा चीन की ओर से भारतीय सीमाओं की सुरक्षा है। किन्तु वर्तमान में कुछ समय से दोनो देशों के मध्य तनाव व सम्बन्धों में खटास का वातावरण पैदा हो गया है। जिसमें नेपाल में नये संविधान निर्माण को लेकर मघेशियों का आन्दोलन, भारत से आपूर्ति वस्तुओं को मघेशियों द्वारा रोके जाना, कालापानी विवाद मुद्दा, सीमा विवाद इसके अतिरिक्त नेपाल में वामपंथी सरकार का गठन जो चीन की ओर अधिक झुकाव रखती है तथा चीन की कर्ज नीति का प्रलोभन, नेपाल में चीन का बढ़ता हस्तक्षेप एवं प्रभाव आदि कारणों से सम्बन्धों में शिथिलता आई है। इसमें भारत सरकार द्वारा नेपाल की ओर अधिक तवज्जों ना दिया जाना भी एक कारण माना जा सकता है। आवश्यकता है कि नेपाल के महत्व को समझते हुए व चीन के बढ़ते हुए दबदबें को रोकने के लिए भारत को अपनी पड़ौस की नीति पर ध्यान देते हुए सुधार, समीक्षा करनी चाहिए। जिससे नेपाल में चीनी प्रभाव को रोका जा सके एवं भारत की सीमाऐं अधिक सुरक्षित रहें।

Indo-Nepal relations are inoffensive type of relations. There has been a cultural, social, spiritual connection since ancient times. This is further enhanced by the 1950 Treaty of Transit. India's attitude towards Nepal has always been supportive. Although there have been differences at times. But they have been resolved. India's relations with Nepal are important. Acts as a buffer state between two superpowers (India-China). Nepal's security is the security of Indian borders from China. But currently for some time, an atmosphere of sourness has arisen in tensions and relations between the two countries. In which the movement of the Magheeshi in Nepal for the creation of new constitution, the supply of goods from India by the Magheesi, the Kalapani dispute issue, the border dispute besides the formation of the leftist government in Nepal which is more inclined towards China and the debt policy of China Relations have slowed due to reasons like the temptation, increased interference and influence of China in Nepal. In this, the government of India not giving more attention to Nepal can also be considered as a reason. There is a need that India should review reforms, while recognizing the importance of Nepal and focusing on its neighbor's policy to prevent the increasing dominance of China. So that Chinese influence in Nepal can be stopped and India's borders should be more secure.

मुख्य शब्द : सामरिक, आर्थिक, सामाजिक सम्बन्ध, सीमा विवाद, लिपुलेख, लिंग्याघूरा, कालापानी, लद्दाख, समीक्षा, नया संविधान, महाराणा, राणाशाही, लोकतंत्र, सुगौली संधि, औखरा घाटी, कोसी बाँध, रक्सौल–काठमाण्डू परियोजना, मधुर सम्बन्ध, पैट्रो–चाइना, जल विद्युत परियोजना, पड़ौसी की नीति, वफर स्टेट, मघेशी आन्दोलन, महाकाली समस्या, वामपंथी सरकार,

संशोधित नक्सा, तनाव, कराकोरम हाइवे, दुर्बुक व श्योक घाटी, कुंजेराव दर्रा, दौलतवेगगोल्डी हवाई पट्टी, ल्हासा, काशगर, हसन अब्दाल, बाल्टिस्तान।

Strategic, Economic, Social Relations, Boundary Disputes, Transcripts, Lingyaghura, Kalapani, Ladakh, Review, New Constitution, Maharana, Rana Shahi, Democracy, Sugauli Pact, Okhara Valley, Kosi Dam, Raxaul-Kathmandu Project, Sweet Relations, Patro-China, Hydropower project, neighborhood policy, wafer state, magheshi movement, Mahakali problem, leftist government, Modified Naksa, Tension, Karakoram Highway, Durbuk and Shyok Valley, Kunjerao Pass, Daulatweggoldi airstrip, Lhasa, Kashgar, Hasan Abdal, Baltistan.

प्रस्तावना

नेपाल राज्य की स्थापना 1769 में पृथ्वी नारायण शाह ने की थी। नेपाल भारत–चीन के मध्य बफर स्टेट के रूप में काम करता है। तिब्बत के हड़प लेने पर भारत की सुरक्षा के लिए नेपाल का महत्व बढ़ गया है। 1950 में नेहरू एवं 1956 मे राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि नेपाल की शान्ती सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा भारत की शान्ती – सुरक्षा के लिए खतरा है। ब्रिटिशभारत शासनकाल के समय से ही नेपाल स्वतंत्र राष्ट्र रहा है। यद्यपि शासन में अंग्रेजो का काफी हस्तक्षेप होता था। सामरिक दृष्टि से नेपाल का भारत के लिए महत्व है। इसी कारण 1950 से ही नेपाल के प्रति भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र की नीति सहयोगी की रही है और उसे शीत युद्ध क्षेत्र बनने से बचाया है। भारत ने 1947 एवं 49 में नेपाल में लोकतांत्रिक, संविधान बनाने का सहयोग किया। 1949 मे नेपाल के साथ संधि करके वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था किन्तु नेपाल के प्रधानमंत्री राणा समसेर जंग ने, जो नेपाल के राजा की सारी शक्तियों का प्रयोग करते थे, इसे स्वीकार नही किया क्योंकि उनकी परम्परागत सत्ता को चुनौती पैदा हो सकती थी।

1950 में राणाशाही के विरूद्ध नेपाल में गृहयुद्ध छिड़ गया और महाराजा त्रिभुवन ने अपने परिवार सहित भारत में शरण ली। भारत के सहयोग से राणाशाही शासन का अन्त हुआ और सत्ता वास्तविक महाराणा के हाथ में आई और वहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ। भारत के अथक प्रयासों से ही 1955 मे नेपाल को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिल सकी थी। 31 जुलाई 1950 को भारत – नेपाल के मध्य मैत्री संधी हुई जिसके आधार पर दोनो देशों के संबंध निर्धारित हुए। इसके अनुसार दोनो देशों की सीमा एक दूसरे के नागरिकों के लिए खुली रहेंगी और उन्हे एक–दूसरे के देशों में बिना रोक–टोक रहने और काम करने की अनुमति होगी। यह संधी दोनो देशों के बीच एक गहरी मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करती है। यह व्यापारिक संधी का आधार बनी। 1951 के बाद भारतीय विशेषज्ञों के माध्यम से नेपाल की सेना को प्रशिक्षण देना, कोसी नदी बांध बनवाना, विकास कार्य करवाना, सड़क रेल विकास, तकनीकी लोगों द्वारा सहयोग किया जा रहा था। 1953–54 में इसे लेकर नेपाल की जनता को भ्रम हो गया कि यह भारतीय हस्तक्षेप हो रहा है। जबकि भारत ने बिना शर्त ही नेपाल के आमंत्रण पर सहयोग दिया था। 1955–56 में नेपाल के महाराजा ने भारत की तथा भारतीय राष्ट्रपति ने नेपाल की यात्रा की और मैत्री सम्बन्धों को और प्रगाढ़ किया था। 1955–56 में नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा ने चीन की यात्रा की गई थी। चीन ने नेपाल को स्वतंत्र सम्प्रभू बनाने तथा आर्थिक सहायता करने की बात की थी।

इसके अतिरिक्त एवरेस्ट पर्वत समझौता किया गया था। भारत ने इसकी तीव्र आलोचना की थी। उसी समय चीन ने कोईराला मंत्री मण्डल भंग करा दिया जिसने भारत में आकर शरण ली थी। इस कारण उस दौर में भारत–नेपाल के सम्बन्धों में कडवाहट आ गई थी। जो 1961 तक बनी रही। नेपाल के महाराजा ने चीन की यात्रा की और ल्हासा–काढमाण्डू–सड़क समझौता किया था। जब 1962 में भारत–चीन युद्ध हुआ तो नेपाल तटस्थ बना रहा था। जिसे भारत ने सही नही माना। भारत – चीन युद्ध से नेपाल भी चीनी आक्रामकता के प्रति चौकन्ना हो गया। 1962 में भारत के गृहमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, बाद में राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने नेपाल की यात्रा की थी और नेपाल के संदेहो को दूर किया गया। नेपाल सरकार ने भी आश्वस्त किया कि नेपाल के मार्ग से भारत पर कोई आक्रमण नहीं होगा। 1964 में भारतीय विदेशमंत्री स्वर्णसिंह ने नेपाल यात्रा की और सुगौली (भारत) से औखरा घाटी (नेपाल) को जोड़ने वाली सड़क निर्माण, काठमाण्डू से रकसौल (भारत) को जोड़ने वाली योजना की सहमति बनी व कोसी बाँध योजना पूर्ण करने की सहमति बनी थी।

1965 मे नेपाल नरेश ने भारत की यात्रा की ओर भारत द्वारा विकास कार्य में दिये जा रहे सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। इसके बाद 1962 में सूर्य बहादुर थापा प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की और सम्बन्धों को आगे बढ़ाया। 1966 में श्रीमति इंदिरा गाँधी नेपाल की यात्रा पर गई और सम्बन्धों को मधुर बनाया गया। सीमा को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुए। 1971 मे भारत की जीत ने नेपाल को प्रभावित किया। सिक्किम के विलय 1974–75 से नेपाल आशंकित हुआ किन्तु भारत ने कहा कि सिक्किम की परिस्थियाँ अलग है, 1975 की महाराजा वीजेन्द्र की भारत यात्रा के दौरान नेपाल को आश्वस्त करते हुए पंचवर्शीय योजनाओं में पूर्ण सहयोग करने को कहा गया। प्रधानमंत्री तुलसीगिरी की 1976 की भारत यात्रा के दौरान भारत ने नेपाल की समदूरी सिद्धान्त (भारत, चीन के प्रति) को अनुचित बताया और भारत के सम्बन्ध नेपाल के साथ विशेष होने पर बल दिया। जनता पार्टी सरकार (1977–79) के दौरान नेपाल के प्रति और उदारता का दृष्टिकोण अपनाया और उद्यौगिक क्षेत्र में विकास का समझौता किया गया तथा नेपाल से कलकत्ता तक व्यापार के लिए सड़क मार्ग की सुविधा दी गई।

अध्ययन का उद्देश्य

भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, भारत के पड़ौसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध बने रहने पर ही चीन जैसी महाशक्ति का मुकाबला किया जा सकता है। भारत–नेपाल सम्बन्धों की समीक्षा एवं सुधार किया जाना आवश्यक है। परम्परागत पड़ौसी मित्रों को अपने पक्ष में व प्रभाव क्षेत्र में बनाये रखना महत्वपूर्ण सामरिक

नीति होगी एवं समीक्षात्मक, सुझावात्मक विश्लेषण करना है।

विषय विस्तार

नेपाल नरेश ने 1985 में भारत की यात्रा के दौरान पारगमन की संधि को 5 वर्श को बढ़ाते हुए 1989 तक कर दिया। किन्तु 1989 में संधि समयावधि समाप्ति से 1991 तक कोई संधि नहीं रही थी। इस बीच अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। 1991 मे पुनः नये सिरे से संधि की गई 1995 तथा 1996 में नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने भारत की यात्रा की और व्यापार व पारगमन संधि को आगे बढ़ा दिया गया। इसी क्रम में भारतीय प्रधानमंत्री इन्द्रकुमार गुजराल ने नेपाल की यात्रा की और विद्युत, व्यापार और नागरिक उड्डयन व महाकाली संधि का अनुमोदन किया गया। बाद में पारगमन संधि को 2006 तक बढ़ा दिया गया। वाजपेई के शासन काल तथा यूपीए सरकार के शासन काल में भारत–नेपाल के सम्बन्ध मधुर बने रहें यद्यपि इस काल में नेपाल में राजशाही शासन का अंत हुआ एवं प्रजातंत्र सरकार का गठन हुआ। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत को आश्वासन दिया कि नेपाल भारत विरोधी किसी भी गतिविधि के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा। 2014 के बाद भारत में सत्ता बदली और 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री ने नेपाल की यात्रा की एवं संविधान सभा व संसद को संबोधित करते हुए आश्वस्त किया कि भारत नेपाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और हर प्रकार का सहयोग करेगा। 2015 मे नेपाल में आये भूकम्प के बाद ''ऑपेरशन मैत्री'' के तहत सहायता पहुँचाई तथा हजारों लोगों की जान बचाई। नेपाल के नये संविधान के तहत भारत की सीमा से लगे तराई क्षेत्र के मधेश क्षेत्र के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिये जाने के कारण मधेशी आन्दोलन 2015 में शुरू हो गया।

नेपाल सरकार ने मधेशियों के साथ वर्वरता का व्यवहार किया। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन में 5 नबम्वर 2015 को नेपाल में बढ़ती हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता तथा बढ़ते भेदभाव की शिकायत की। इसी बीच मधेशियों ने भारत की सीमा से ट्रकों की नेपाल आवाजाही को अवरूद्ध कर दिया। इससे नेपाल में पेट्रॉल, गैस, खाद्य सामग्री आदि की कमी आ गई। नेपाली प्रधानमंत्री ने इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। भारत से होने वाले पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में भारी कमी आने के बाद नेपाल ने 28 अक्टूबर 2015 को ''पैट्रो चाइना'' के तहत पैट्रोलियम और गैसोलीन आपूर्ति के दो समझोते चीन के साथ किये। इस प्रकार चीन ने परिस्थिति का लाभ उठाते हुए नेपाल के भारत विरोधी रूख को और मजबूत किया। भारत ने मधेशी आन्दोलन व गैस पैट्रोलिय आदि की कमी के लिए नेपाल को जिम्मेदार ठहराया। दोनो देशों के बीच कटुता बन गई थी।

अगस्त 2017 में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भारत की 5 दिवसीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भी देउबा ने संयुक्त रूप से कटैया–कुसहा और रक्सौल–पखानीपुर विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनसे नेपाल को 100 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली आपूर्ति हो सकेगी। इस यात्रा के दौरान दौनो देशो के बीच कई समझौते हुए–

1. नेपाल में भूकम्प के बाद पुनर्निर्माण पैकेज में एक अरब डालर की सहायता में से 50 हजार आवासों के निर्माण के अनुदान को आवश्यकतानुसार प्रयोग तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक धरोहर के लिए उपयोग कर सकेंगे।
2. मेची नदी पर पुल–निर्माण के लिए लागत समझौता हुआ।
3. नशीले पदार्थो तथा प्रतिबंधित रसायनों की तस्करी रोकने हेतु समझौता।
4. भारत के सहयोग से नेपाल में स्थापनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं को तय समय में में पूरा करने के लिए प्रयासों में तेजी लाने में दोनो प्रधानमंत्रियों में सहमति बनी।

इसके अतिरिक्त नेपाल ने विश्वास दिलाया कि वह खुली सीमा होने के बावजूद अपनी भूमि पर भारत के विरूद्ध किसी भी गतिविधि को इजाजत नहीं देगा।

फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री पद पर चुने जाने के पश्चात् भी ओली ने पहली यात्रा भारत की की थी। अप्रेल 2018 में नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली भारत की यात्रा पर आये थे। इसमें दोनो देशो के मध्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, रेल्वे लिंकेज व इनलैण्ड वाटर वेज आदि मामलों में सहयोग की सहमति बनी। संयुक्त बक्तव्य जारी किया भारत–नेपाल कृषि में नई साझेदारी, रेल सम्पर्को के विकास, भारत में रक्सौल को नेपाल में काठमाण्डू से जोड़ने तथा भारत–नेपाल के बीच आन्तरिक जलमार्गो के जरिये नये सम्पर्क साधने से सम्बन्धित है, समझौता हुआ। यात्रा को सफल बताते हुए भी ओली ने कहा कि वार्ता से दोनो देशो के सम्बन्ध सुधरे है। दोनो के मध्य गलत फहमियाँ तथा अविश्वास दूर हुआ है।

उल्लेखनीय है कि श्री के पी शर्मा ओली वामपंथी है तथा चीन के प्रति अधिक झुकाव रखते है। भारत के आलोचक है और आंतरिक हस्तक्षेप का आरोप भारत पर लगाये थे। अपनी सरकार गिराने के आरोप भी लगाये थे। मई 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की यात्रा की तथा तीन माह बाद बिमस्टेक सिखर सम्मेलन में भागीदारी के लिए भी नेपाल की यात्रा की। दोनो देशों के मध्य जनकपुर–अयोध्या बस सेवा शुरू की गई जिससे दोनो देशों के पौराणिक सम्बन्ध प्रगाढ़ता से बने रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजा जनक व दशरथ ने दोनो देशों के मध्य मैत्री सम्बन्ध बनाये थे। इस अवसर पर उन्होने जनकपुर के आस–पास के क्षेत्रों के विकास के लिए 100 करोड़ की मदद उपलब्ध कराने की घोषणा भी की। इसके अतिरिक्त पाँच T ट्रेडिसन, ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी व ट्रांसपोर्ट पर बल दिया था। अप्रेल 2018 की यात्रा के दौरान जिन विषयों पर सहमति बनी थी उनके प्रति प्रतिबद्धता को दुहराया। विद्युत व्यापार समझौते के तहत अरूण नदी पर 900 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना की शुरूआत की। इसके अतिरिक्त 500 एवं 1000 के भारतीय नोटो के नेपाल में पड़े होने के

समाधान की बात हुई। सीमा पर रक्षा तथा सुरक्षा बढ़ाने की साझा कोशिसों पर सहमति बनी।

वर्तमान में भारत–नेपाल सम्बन्ध)

भारत नेपाल के सम्बन्ध लम्बे समय से मधुर रहे है, किन्तु इनके सम्बन्धों को सही तरह से समझने के लिए चीन की नीतियों को भी ध्यान में रखना होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष में चीन न केवल नेपाल में अपना दवदवा बढ़ा रहा है बल्कि भारत के सभी पड़ौसी देशो यथा वंगलादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान तथा म्यानमार आदि में अपने वर्चस्व के लिए गतिविधियाँ बढ़ा रहा है। चीन एसियाई देशो में भारत को अपना प्रतिद्वंदि मानता है और इसी को दृष्टि में रखते हुए भारत के पडौसी देशो में कर्जनीति, बंदरगाह विकास नीति आदि का सहारा लेकर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में लगा हुआ है। नेपाल के साथ भी आर्थिक व्यापरिक सम्बन्ध बढ़ा कर उसे अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है तथा भारत के विरूद्ध उकसाने लगा है। नेपाल में व्यापारिक अड्डे स्थापित करके, कर्ज देकर अपना पिछलग्गू बना रहा है। चीन के सहयोग से ही बामपंथी सरकार स्थापित हुई है और उसको येन केन बनाये रखना चाहता है। इसीके उकसाने पर कालीनदी सीमा विवाद नेपाल ने खड़ा किया है। भारत के लिए नेपाल एक बफर स्टेट के रूप में महत्व पूर्ण देश है और इसी कारण भारत ने हमेशा नेपाल के विकास में सहभागिता की है तथा मधुर सम्बन्ध बनाये रखने का प्रयास किया है। किन्तु 2015 के बाद दोनो देशो के बीच सम्बन्ध तनाव की ओर अग्रसर है। जिसके अनेक कारण देखे जा सकते है।

भारत–नेपाल के विगड़ते रिश्तों के कारण

यद्यपि भारत–नेपाल के सम्बन्ध खास माने जाते हैं। यहां तक कि भारतीय सेना में 38 इंफैन्ट्री यूनिट्स नेपाल के मशहूर गोरखाओं की है और लगभग 38000 नेपाली गोरखा भारतीय सेनामें सेवाऐ दे रहे है। इनके लिए नेपाल में भारत ने उनकी भर्ती एवं पेंशन ऑफिस बनाया हुआ है। गोरखा सैनिक जम्मू–कश्मीर सीमा क्षेत्र में एक प्रहरी के रूप में अपनी सेवायें देते है। 1950 की संधि के तहत नेपाली नागरिक भारत में भारतीय नागरिकों की सभी सुविधाऐं लेते है। किन्तु भारत–नेपाल के विगड़ते सम्बन्धों के पीछे कारण है कि नेपाली राजनेता नेपाल के रणनीतिकहितो को पूर्ण नियंत्रण करने की महत्वाकांक्षा रखने लगें है, उन्हे लगता है कि यह भारतीय हितों के अधीन है दूसरा नेपाल के चीन के साथ बढ़ते सम्बन्ध भी कारण है। नेपाल दोनो एसियाई शक्ति (भारत–चीन) से अपनी भूरणनीतिक स्थिति का पूर्ण फायदा उढ़ाना चाहता है। जब सिक्किम का विलय भारत में हुआ तब से नेपाल में अपने लिए शंका उत्पन्न हुई और नेपाल को 'शांतिक्षेत्र' घोषित कराने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाता रहा है। जिसका चीन, पाक सहित अनेक देशों ने समर्थन किया था। इस प्रकार नेपाल में बढ़ते नस्लीय राष्ट्रवाद की बजह से 1990 में व्यापार और परिवहन समझोते भारत के साथ भंग हो गये और दोनो देशों की मुद्रा अलग–अलग हो गई। इस कारण भारत को मजबूर होकर नेपाल के लिए कोलकता बंदरगाह की सेवाऐं बंद करनी पड़ी थी। जिससे नेपाल की जी डी पी के आँकडे 9.5% से गिरकर 1.5% पर आगये थे। नेपाल द्वारा चीन से हथियार आयात किया जाना भी सम्बन्धों में कमजोरी का कारण रहा था। हांलाकि बीच–बीच में सम्बन्ध संभलते भी रहे किन्तु खटास भी बढ़ती रही क्योंकि नेपाली सरकार अपनी कूटनीतिक स्वायत्तता साबित करने के लिए चीन को भी बराबर महत्वपूर्ण साझेदार दिखाने का प्रयास करती रही है। हांलाकि भारत को चीन के बढ़ते दबदवे की ओर ध्यान देना चाहिए था और नेपाल के लिए कुछ करने की आवश्यकता भी थी जिससे वह भारत के प्रभाव क्षेत्र में रहता।

भारत–नेपाल सम्बन्धों में मतभेद हाल के वर्षो में ज्यादा देखने को मिल रहे है। जब 2015 में नेपाल के संविधान मसौदे को लेकर मधेसियों ने आन्दोलन किया था, तब भारत–नेपाल सीमा कई दिनो तक ठप रही थी। नतीजतन, नेपाल ने अपनी कुछ महत्वपूर्ण सीमा चौकियों पर भारत द्वारा आर्थिक नाकेबंदी का आरोप लगया जिसके भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। इस कारण कुछ महिनो तक दोनो देशों के बीच आरोप–प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। इसके बाद फरवरी 2016 में नेपाली प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने भारत का दौरा किया और भारत के साथ बेतहर सम्बन्धों की प्रतिवद्धता दोहराई थी। यात्रा के दौरान में भारत नेपाल के बीच द्विपक्षीय शिखर बैठक हुई और 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। इससे ऐसा लगा कि शायद दोनो देशों के बीच तनाव का दौर खत्म हो गया है। किन्तु तभी नेपाल और चीन दोनो एक–दूसरे में दिलचस्पी दिखाने लगें। इसी बीच नेपाल में राजनीतिक उठापटक के बाद सत्ता बदली और आखिरकार के. पी. शर्मा ओली फिर से प्रधानमंत्री बन गये। जून 2018 में नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने चीन की यात्रा की और दोनो देशो के बीच 14 मुद्दो पर समझौता हुआ। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन–तिब्बत रेल लिंक समझौता सबसे महत्वपूर्ण था। इसके अलावा चीन नेपाल में बड़ी मात्रा में निवेश कर रहा है, जैसे बुनीयादी ढाँचा, सड़क, बिजली आदि कई परियोजनाए चीन द्वारा कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त चीन ने नेपाल को कई चीनी बंदरगाहो को उपयोग करने की भी अनुमति दी है और इन सब कारणों से नेपाल में चीन का दबदवा लगातार बढ़ रहा है व भारत का प्रभाव कम होता दिख रहा है। इससे प्रतीत होता है कि नेपाल सरकार की बढ़ती हुई महत्वकांक्षाऐं भारत–नेपाल के सम्बन्धों में खटास पैदा करती है। चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बाद तिरूपति से लौटते हुए नेपाल में जाना और वार्ता करना, चीन द्वारा नेपाल को महत्व देना ही था।

हाल के वर्षो में नेपाल द्वारा उठाये जा रहे मुद्दे जो कि कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाघुरा से जुड़े मुद्दे हुए है। नेपाल का यह मौजूदा हठ धीरे–धीरे कमजोर होते सम्बन्धों का ही नतीजा है। 18 सितम्बर 2015 को नेपाल ने नया संविधान अपनाया जिससे भारत समेत बडी संख्या में मधेशी नेपालियों को लगा कि नेपाल में रहने वाले भारतीय मूल के मधेशियों का ध्यान नहीं रखा गया है। मधेशी आन्दोलन से नेपाल की मुसीबत बढ़ी और वहाँ ऐसा माना गया कि यह भारत के इशारों

पर हो रहा है। इससे नेपालियों को चीन के साथ ज्यादा व्यापक सम्बन्धों की तरफ जाने का मौका मिला है। खासतौर पर माओवादी प्रभुत्व वाली के. पी. शर्मा ओली की सरकार के साथ। सीमा विवाद मुद्दा तब सामने आया जब भारत ने 10 नबम्वर 2019 को अपने नक्से में कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाघुरा को अपने हिस्से में दिखाया और इसके बाद 8 मई 2020 को लिपुलेख के पास होते हुए कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क का औपचारिक उद्घाटन किया।

नेपाल ने इस कदम का जोरदार विरोध किया। प्रधानमंत्री ओली की कैवीनेट ने 8 मई 2020 को नया राजनीतिक नक्सा जारी करने का फैसला लिया। जिसमें नेपाल ने भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया। नेपाली संसद ने इस पर संविधान संशोधन पारित कर दिया। ऐसा उस समय किया गया जब चीन, भारत पर सिक्किम और लद्दाख में दबाव बना रहा है। सीमा पर कई अपहरण और अतिक्रमण की बाते भी सामने आई है। लिपुलेख–कालापानी क्षेत्र के बारे में जो ओली पहले काफी संयत भाषा का प्रयोग कर रहे थे और भारत से राजनयिक स्तर पर सारे मामले को सुलझाने की बात कर रहे थे, उन्होने भारत पर ऐसे व्यंग बाण वरसाने शुरू कर दिये, जो किसी भी अन्य नेपाली प्रधानमंत्री ने नहीं वरसाये थे। ओली ने कहा कि भारत का नारा ''सत्यमेव जयते'' की बजाय ''सिंहदेव जयते'' होना चाहिए। यानी भारत दंड के जोर पर जमीन हथियाना चाहता है। उन्होने पिछले दिनों भारत पर यह आरोप भी लगाया कि भारत सरकार ओली की सरकार को गिराने का षड़यंत्र कर रही है। ओली ने नेपाली संविधान में संशोधन करके 1816 की सुगोली संधि द्वारा भारत को दिये क्षेत्रों लिपुलेख एवं कालापानी को नेपाल के नक्से में दिखा दिया।

यह सब चीन की सह पर नेपाल द्वारा किया गया है। दोनो के मध्य सीमा विवाद उस समय पैदा हुआ है जब भारत का फोकस लद्दाख पर है जहाँ गतिरोध अभी जारी है। लेकिन भारत को इस बारे में भी चिंता करनी चाहिए। कि नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, मालदीव समेत अन्य पड़ौसी देशों में भी चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। यह वह क्षेत्र है जहाँ भारत के खास हित है और उसे चीन पर निगाह रखनी चाहिए। भारत को ''पहले पड़ौसी'' नीति पर ज्यादा ध्यान देते हुए मजबूत आर्थिक सम्बन्धों और सम्पर्को पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। यद्यपि कालापानी समस्या पहले से ही विद्वमान थी, फिर भी चीन के उकसाने पर नेपाल ने समस्या खड़ी की है। क्योंकि चीन को भारत और उसके पड़ौसियें के बीच तनाव पैदा करना अच्छा लगाता है। वैसे भी चीन हिन्द क्षेत्र में अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। नेपाल में ओली की कम्युनिश्ट पार्टी सत्ता में बनी रहे इसके लिए चीन ने हर सम्भव प्रयास किया है। जबकि भारत ने नेपाल को हमेशा लोकतांत्रिक देश बनाने का सहयोग किया है। नेपाल में स्थिरता व शान्ती भारत के हित में है। किन्तु चीन चाहता है कि पूर्व व दक्षिण चीन सागर में जापान व दक्षिण–पूर्व एसियाई देशों के साथ–साथ हिमालय में नेपाल, भूटान और भारत के लद्दाख, सिक्किम एवं अरूणाचल प्रदेश में चीन की दखलदाजी व आक्रामक नीति चलती रहें। चीन अपने आपको इतना सक्षम मानता है कि वो 19 वीं शताब्दी में उसकी यूरोपीय देशों की एक तरफा संधियों में तय की गई सीमाओं से परे अपनी एकतरफा, सोच पड़ौसी देशों पर थोप सकें। जैसाकि माओ कहता था कि ''तिब्बत हथेली है और लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम तथा अरूणाचल प्रदेश उसकी पाँच उँगली है'' चीन इनको अपने साम्राज्यवाद का शिकार बनाना चाहता है। इसी सोच के चलते चीन ने तिब्बत में किलेबन्दी तथा सीमान्त क्षेत्रों में सैन्य आधारित संरचनाओं का आधुनिकीकरण किया है तथा पड़ौसी देशो के प्रति आक्रामक तेबर एवं बल प्रदर्शन भी करता रहा है। इसमें सबसे ज्यादा सामरिक महत्व के 1300 किलोमीटर लम्बे कराकोरम हाइवे का है जो शिन जियांग के काशगरों को पाकिस्तान के पंजाब में हसन अब्दाल से जोड़ता है।

यह हाइवे कुंजेराब दर्रे से गुजरता है जो– विश्व की सबसे ऊँची सीमा पारगमन वाली पक्की सड़क है। चीन चाहता है कि ल्हासा से वाल्टिस्तान, काशगर होकर न जाना पड़े, इसलिए वह लद्दाख की श्योक घाटी से सीधा रास्ता निकाल ले। यही कारण है कि आज चीन भारत की दौलत बेग गोल्डी हवाई पट्टी पर हो रहे सुधार और दुर्बुक व श्योक घाटी से गुजरने वाली पक्की सड़क जो लेह को दौलत वेग गोल्डी से जोड़ती है, को लेकर बहुत परेशान है। सामरिक नजरिये से यह हवाई पट्टी भविष्य में भारत–चीन–पाकिस्तान के समीकरणों को पूरी तरह से भारत के पक्ष में बदल सकती है। इसलिए चीन न केवल सीमा के कई बिन्दुओं पर तनाव और अस्थिरता फैला रहा है बल्कि नेपाल और भूटान को भी उकसा व धमका कर भारत की परिशानियों को बढ़ाने में लगा हुआ है। यही कारण है कि जब भारत–चीन के सैनिको के मध्य भिड़न्त हो रही थी तभी नेपाल ने भी आक्रामक रूख अपनाते हुए लिपुलेख, लिंग्याधूरा और कालापानी क्षेत्रों पर अपना दावा ठोक दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली का यह अपने आपको चीन के प्रति निष्ठावान दिखाने का प्रदर्शन था। चीन भी नेपाल में औली के नेतृत्व को बरकरार रखना चाहता है। इसके लिए चीनी राजदूत हाऊयान छि का पिछले कुछ समय से नेपाल की अन्दरूनी राजनीति में सीधा–सीधा हस्तक्षेप रहा है और नेपाल द्वारा बनाये गये नये नक्से का समर्थन किया है।

भारत–नेपाल के बीच नवीनतम तनाव ने सम्बन्धों में पड़ी दरार को चौड़ा कर दियाहै। कहने को विवाद भारत–नेपाल सीमा के कालापानी–लिम्पियाघूरा–लिपुलेख त्रिकोण में स्थित कोई 300 वर्ग किलोमीटर भूभाग का है। किन्तु नेपाल में यह धारणा जोर पकड़ गई है कि भारत ने 1962 के भारत–चीन युद्ध के बाद नेपाल के राजा से गुप्त समझौता कर सामरिक दृश्टि से महत्वपूर्ण इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। यह मामला बढ़ गया, जब नेपाल की संसद ने सर्व सम्मति से संविधान संशोधन पास करके नेपाल के एक नये नक्से को संविधान का हिस्सा बना दिया। इस नये नक्से में कालापानी इलाके को नेपाल में दिखाया गया है। अब नेपाल की कोई भी सरकार भारत के साथ कोई समझौता इस सीमा क्षेत्र के सम्बन्ध में करेगी तो कठिनाई होगी क्योकि भारतीय क्षेत्र को भारत

का मानने की समहति देने पर वहाँ के संविधान के विरूद्ध माना जायेगा। यद्यपि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस संशोधन पर कठोर आपत्ती जताई थी। किन्तु सम्बन्धों के बीच यह एक पड़ी गांठ के रूप में होगी। हालांकि यह भी सही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने यह राष्ट्रवाद का पत्ता अपनी लड़खड़ाती सरकार/सत्ता को बचाने के लिए खेला था। इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इसके पीछे भी चीन की शह थी। किन्तु आगे दोनो देशों के सम्बन्धों में यह संशोधन(नक्सा) खटास पैदा करेंगा। किन्तु दूसरा यह भी पहलू है कि नेपाली मानस में भारत सरकार की दादागिरी के खिलाफ पुरानी और गहरी शिकायत है। एक साधारण नेपाली को लगता है कि भारत सरकार उसके देश को सार्वभौम देश मानने को तैयार नहीं है, बल्कि उसे सिक्किम और भूटान जैसा समझती है। भारत का विदेश मंत्रालय नेपाल के अंदरूनी मामलों में नाजायज दखल देता है। वहाँ सरकार बनाने या गिराने के खेल में शामिल रहता है। वर्ष 2015 में नेपाल की नाकाबंदी का दर्द वहाँ के नागरिक भूले नहीं है। वहाँ कई साल से ''भारतीय साम्राज्यवाद'' के विरोध का नारा नेपाली राजनीति में खूब चलता है। कालापानी मुद्दा इस गहरे मानसिक अलगाव का प्रतीक बन गया है।

भारत के बिगड़ते रिस्तो में भूमिका एवं सुझाव

भारत–नेपाल के बीच रिस्तो में बढ़ती दरार को रोकने के लिए भारत को नेपाल की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि भारत–नेपाल सम्बन्धों में बढ़ते मतभेदों के कारण एकतरफा नहीं है। दोनो देशों के सम्बन्धों में कड़वाहट तब आई जब सितम्बर 2015 में नेपाली संविधान अस्तित्व में आया था। लेकिन भारत द्वारा नेपाली संविधान का उस रूप में स्वागत नहीं किया गया जिस रूप में नेपाल को आशा थी। इसी तरह नवम्बर 2015 में जेनेवा में भारतीय प्रतिनिधित्व द्वारा नेपाल में राजनीतिक फेर बदल को प्रभावित करने के लिए मानवाधिकार परिषद के मंच का कठोरता पूर्वक उपयोग किया गया। जबकि इससे पहले तक नेपाल के आंतरिक मुद्दों को लेकर भारत द्वारा कभी भी खुलकर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त भारतीय वार्ताकारों द्वारा नेपाली कांग्रेस पर मुख्य धारा में शामिल CPN (कम्यूनिश्ट पार्टी नेपाल) का साथ छोड़कर पुष्प कमल दहल को माओवादी पार्टी के साथ गठबन्धन बनाने का दबाव भी डाला गया। इसी प्रकार पहले भारत का रूख मधेशियों को नेपाल में नागरिकता का अधिकार दिलाना था, किन्तु बदलते समय के साथ–साथ भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए अपने कदम बापस खींच लिए है। गौरतलब है कि नेपाल में मधेशियों की संख्या लगभग 1.25 करोड़ है। इनमें से लाखों मधेशियों ने 2015 में नागरिकता को लेकर व्यापक आन्दोलन चलाया था। इसके अलावा 2008 में भारत और नेपाल के बीच जब शांति प्रक्रिया का दौर चला, तब नेपाल में एक नये संविधान के मसौदे पर कार्य शुरू हुआ था। इस दौरान लगभग सभी नेपाली प्रधानमंत्रियों ने भारत का दौरा किया और कुछ तो एक से अधिक वार भी दौरे पर आये थे। किन्तु भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा रिश्ते में गर्मजोशी नही दिखाई गई थी। भारत के इस रवैये से समझा गया कि नेपाल नई दिल्ली की विदेश नीति की प्राथमिकता में नहीं है। ये कुछ ऐसे पहलू है कि जिनकी वजह से भारत–नेपाल सम्बन्धों में दरार बढ़ती चली गई। हाँलांकि इस दौरान भी दोनो देश के प्रधान मंत्रियों ने एक दूसरे देश की यात्राऐं भी की किन्तु कोई ठोस प्रभावी बात नहीं की गई थी। दूसरी तरफ चीन अपना प्रभाव निरंतर नेपाल में बढ़ाता रहा है और प्रधानमंत्री ओली का रूझान भी चीन की तरफ अधिक हो गया है। दरअसल, नेपाल द्वारा बार–बार भारत की उपेक्षा करने के पीछे अनेक कारक काम कर रहे है। नेपाल में चीन का बढ़ता हस्तक्षेप, नेपाल की आन्तरिक राजनीति और भारत की पड़ौस नीति की समस्या कुछ ऐसे पहलू है जो दोनो देशों में मतभेदों के कारण बन रहे है। जहाँ तक चीन का सवाल है तो, उसने पिछले कुछ समय से नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश और मालदीव में अपनी सक्रियता बढ़ाई है। वह पाकिस्तान सहित सभी सार्क देशों को आर्थिक सहायता का लालच देकर अपने प्रभाव में लाना चाहता है। नेपाल में चीन द्वारा भारी निवेश इसी का उदाहरण है। अगर नेपाल की आन्तरिक राजनीति की बात करें तो वहाँ पिछले 10 वर्षो से अनेक बार सत्ता परिवर्तन हो चुकी है। जाहिर है कि नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता उसकी विदेश नीति को संभलने नहीं दे रही है। वहाँ एक शसक्त और मजबूत नेतृत्व की जरूरत है जो कि पड़ौसी देशों के साथ वेहतर सम्बन्ध बना सके। यह भी सच है कि भारत और चीन के साथ नेपाल एक आजाद सौदागर की तरह व्यवहार कर रहा है और चीनी निवेश के सामने भारत की चमक फीकी पड़ रही है। लिहाजा भारत को कूटनीतिक सूझ–बूझ का परिचय देना होगा। बात चाहे विमस्टेक देशों की हो या सार्क देशों की, भारत से हमेशा उम्मीद की जाती है कि वह एक नेतृत्व कर्ता की तरह काम करें। किन्तु भारत इस उम्मीद पर खरा नहीं उतर पा रहा है। अनेक वादे तो भारत सरकार कर देती है किन्तु उनकी सही और समय पर परिणति नहीं की जाती है और चीन इसी का फायदा उठाता है। भारत को चाहिए कि वह रक्सौल – काठमाण्डू रेल लिंक परियोजना को तथा मोतिहारी – अमेलखगंज तेल पाईपलाईन जैसी योजनाओं को समय पर और तत्परता से पूरा करें। चीन भारत के पड़ौसी देशो में पहुँच बनाने के लिए किसी भी अवसर को छोड़ना नहीं चाहता है। वर्तमान में भारत–नेपाल के सम्बन्धों में जो गांठ पड़ गई है उसके लिए हमारी ''पड़ौस की विदेशनीति'' की समीक्षा करने की आवश्यकता है। हमें नेपाल के प्रति तथा अन्य पड़ौस के देशों के प्रति नरम दिली दिखाते हुए अपने पक्ष में रखना जरूरी है। भारत–नेपाल के अनूठे सम्बन्धों को केवल विदेशनीति के खाँचे में समझा नही जा सकता है। हम दो ऐसे पड़ौसी देश है जो एक–दूसरे के रिश्तेदार भी है तथा प्राचीनकाल से ही भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आधात्मिक सम्बन्धों के कारण आपसी जुड़ाव रहा है। भारत–नेपाल का रोटी–बेटी का रिश्ता माना जाता है तथा नेपाल के मधेशियों का सांस्कृतिक एवं नृजातीम जुड़ाव भारत के साथ रहा हे। दोनो देशों की सीमाओं से यातायात पर कभी कोई विशेष

प्रतिवंध नहीं रहा है। सामाजिक, आर्थिक विनिमय बिना किसी गतिरोध के चलता रहा है। भारत–नेपाल की सीमा खुली हुई है और आवागमन के लिए किसी पास पोर्ट या बीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब उदाहरण भारत–नेपाल की नजदीकियों को दर्शाते है। किन्तु जो मतभेद/तनाव दोनो देशों के बीच बढ़े है उन्हे रोकना दोनो पक्षों के हित में है। नेपाल को खुली सीमा व भारतीय अर्थव्यवस्था से सम्बन्ध बनाये रखने की जरूरत है तो भारत को भी चीनी सीमा पर एक दोस्त की जरूरत है। इधर चीन ने अपने आर्थिक और सैन्य शक्ति के बल पर लद्दाख में आक्रामता दिखानी शुरू की है, उधर बाकी सब पड़ौसियों से भारत के सम्बन्धों में खटाश पैदा हो रही है। भूटान, बंगलादेश और श्रीलंका जैसे परम्परागत मित्र पड़ौसीयों के साथ भी सम्बन्धों में तनाव पहले से अधिक बढ़ा है। ऐसे में नेपाल के साथ खुले तनाव होने का मतलब होगा कि भारत चारो तरफ पड़ौसियों के झगड़े में घिरा होगा। चीन इसी मौके की तलाश में है। इसलिए सम्बन्धों को मधुरता की ओर लाने की आवश्यकता है। अगर भारत आक्रामक रूख अपनाता है तो नेपाली केवल चीन को ही गले लगायेंगे।

निष्कर्ष

हालांकि भारत सरकार ने नेपाल सरकार के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते भी किये है जैसे कृषि, रेलवे सम्बन्धी और अन्तर्देशीय जल मार्ग विकास आदि। इनमें विहार के रक्सौल और काठमाण्डू के बीच सामरिक रेल्वे लिंक का निर्माण कार्य तथा मोतीहारी से नेपाल के अमेलखगंज तक दोनो देशों के बीच आयल पाइप लाईन विछाने पर सहमति होना, इसके अलावा 2015 में नेपाल में आये भूकम्प के समय राहत सामग्री एवं NDRF के जवानों को सहायता के लिये भेजे जाना आदि। किन्तु ऐसे समझौते जल्दी अमल में लाये जाने चाहिए ये शिर्फ वायदे सुहाने सपने बन कर रह जाते है। वैसे भी वर्तमान की नई तकनीक की चकाचौंद में अपर्याप्त सहयोग है। चीनी तकनीक तथा विकास कार्य के आगे भारतीय सहयोग की पहचान कमजोर पड़ रही है। भारत को नेपाल क साथ नये सिरे से सम्बन्धों की समीक्षा करने की जरूरत है। इससे चीन की कर्जनीति, तकनीक, प्रलोभन नीति को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *डॉ0 फाडिया, बी एल, ''अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति'' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा*
2. *डॉ0 फाडिया, बी एल, ''अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध'' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा*
3. *डॉ0 जैन, पुखराज, ''प्रमुख राजव्यवस्थाए'' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा*
4. *डॉ0 सिंहल, एम पी, ''अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध'' लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा*
5. *डॉ0 जोशी, आर पी एवं अग्रवाल, अनीता, ''अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध'' शील संस प्रकाशन, जयपुर*
6. *खण्डेला, मानचन्द, ''भारतीय राजनीति का भविष्य'' अरिहन्त पब्लिसिंग हाउस, जयपुर*
7. *अतिरिक्तांक, प्रतियोगिता दर्पण 2019, समसामायिक वार्षिकी*
8. *अतिरिक्तांक, प्रतियोगिता दर्पण 2020, समसामायिक वार्षिकी*
9. *इन्टरनेट – मुक्त ज्ञान कोष, विकिपीडिया*
10. *डॉ0 सिंह, रहीस, विदेश मामलो के विशेषज्ञ का लेख, दैनिक भास्कर, दिनांक 13.09.2020*
11. *लेफ्ट जनरल, हसनन, एसए, कश्मीर में 15 वीं कोर के पूर्व कमांडर का लेख, दैनिक भास्कर, दिनांक 25. 07.2020*
12. *दैनिक भास्कर की ग्राउण्ड रिपोर्ट – दिनांक 17.06. 2020*
13. *डॉ0 वैदिक, वेद प्रताप, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष का लेख, दैनिक भास्कर, दिनांक 04.07. 2020*
14. *डॉ0 सिंह, स्वर्ण, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, जे एन यू नई दिल्ली का लेख, राजस्थान पत्रिका, दिनांक 09.07.2020*
15. *डॉ0 जेवियर, कॉन्सटैनटिनो, फॉरेन पॉलिसी स्टडीज, रिसर्च स्कॉलर, ब्रूकिंस इण्डिया का लेख, दैनिक भास्कर, दिनांक 27.06.2020*
16. *डॉ0 यादव, योगेन्द्र, सैफोलॉजिस्ट और अध्यक्ष, स्वराज इण्डिया का लेख, दैनिक भास्कर, दिनांक 17. 06.2020*
17. *NIC, Internet, Google*